

रांची, सोमवार

20.02.2017

फाल्गुन कृष्ण 10 संवत् 2073

पृष्ठ 22, मूल्य : ₹ 5

नगर संस्करण

वर्ग : 33, अंक : 50, रजिस्ट्रेशन : आर एन 44208/84

prabhatkhabar.com

प्रभात खबर

अखबार नहीं आंदोलन

झारखंड का सर्वाधिक प्रसारित दैनिक : रांची। पटना। जमशेदपुर। धनबाद। देवघर। कोलकाता। सिलीगुड़ी। मुजफ्फरपुर। भागलपुर। गया से प्रकाशित

स्पोर्ट्स : एकता के पांव विकेटों से भारत फाइनल में, पाकिस्तान हारा

16

देश-विदेश : आइएस को हरायेंगे, अपनी सेना का पुनर्निर्माण करेंगे : टूट

15

अंतरिक्ष यान में पृथ्वी का पहला चक्कर

- 20 फरवरी, 1962 को एक अमेरिकी अंतरिक्ष यान जोन ग्लेन ने अंतरिक्ष यान में बैटकर पहली बार पृथ्वी का चक्कर लगाया था।
- उन्होंने पोलोरीस के केपेरीस सेक्टर से फेजिंग - 7 अंतरिक्ष यान से खाना शुरू की थी।
- अंतरिक्ष कार्यक्रमों में रूस से प्रतिस्पर्धा के खरूना अमेरिका में इस अभियान को एक बड़ी उपलब्धि के रूप में मान्यता मिली और जोन ग्लेन हीरो बन गये।
- पृथ्वी से लगभग 162 मील की ऊंचाई पर इस यान ने पृथ्वी के तीन चक्कर कटे। चार घंटे 55 मिनट और 23 सेकंड की यात्रा पूरी कर यान सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौट आया।



राजू राजाराम और नैं का मंचन

जानेमाने सिने अभिनेता शरमन जोशी ने रविवार को राजू राजा राम और मै हास्यनाटक का रिमून्ड प्रकाश में मंचन किया। केदार शिंदे द्वारा लिखित यह नाटक मराठी का प्रसिद्ध नाटक सही रे सही का हिंदी रूपांतरण है। शरमन जोशी ने मदन मनसुखानी के स्क्रिप्ट के चार किटकारों को रोचक अंदाज में पेश किया। जो दर्शकों को पसंद आया। नाटक में मृत मदन मनसुखानी की वसीयत पर दावा करनेवाले उसके हम्माखल को लोते हैं, जिनका खुलासा हो जाता है। देखें लाइव कवरेज

आइपीएल 2017

धौनी की जगह स्मिथ पुणे टीम के कप्तान



कोलकाता, फाल्गुन चार आइपीएल में पूर्व भारतीय कप्तान महेश सिंह धौनी क्रिकेट के लिए पर रिस्का लगे। रविवार को धौनी को उनकी फ्रेंचमाइंडेड युद्धमित्र पुणे सुपरजाइंट्स ने कप्तान पद से हटा दिया है। आइस्टीव्स स्टॉन स्मिथ के आइपीएल में इस साल के शुरू में भारत की सीमित ओवरों की टीम को कप्तानी छोड़ दी थी, लेकिन वह टीम में बने हुए हैं। इसी तरह से वह पुणे फ्रेंचमाइंडेड की तरफ से एक खिलाड़ी के रूप में खेलते रहेंगे। ● चेन्नई 16 पर

ब्रीफिंग

घरों में शौचालय नहीं, तो निकाह नहीं : मदनी

मुवाखरी, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश व पंजाब के भोलावर्ष व मुनिशियों ने फैसला किया कि वे ऐसे घरों के लड़कों को निकाह नहीं करावेंगे, जिनके घरों में शौचालय नहीं है। जमीन उलम ए हिंद के महासचिव मोलाना महमूद ए मदन ने कहा कि तीन राज्यों में शौचालय की शर्त को मुस्लिमों की शादी के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। इसे जल्द ही देश के अन्य सभी राज्यों में लागू किया जाएगा। पूर्व राज्यसभा सदस्य मदन ने यह बात छिछले हफ्ते यहाँ खानापड़ा में स्वच्छता पर

लोहार को एसटी का दर्जा नहीं

विशेष संवाददाता : रांची

राज्य सरकार लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं देती। उसे पहले की तरह ही राज्य में पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र मिलेगा। सरकार ने टीआरआर की रिपोर्ट और लोहार जाति के आवेदन पर सभी पक्षों की सुनवाई के बाद यह फैसला किया है। लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा की मांग एकीकृत बिहार के समय से ही उठती रही है। राज्य में लोहार को पिछड़ी जाति और लोहार को एसटी का दर्जा प्राप्त है। लोहार गठन के बाद लोहार जाति को एसटी का दर्जा दिये जाने की मांग तेज हुई। हालांकि पिछले दिनों सरकार ने इस मांग पर विचार करना शुरू किया। उसने जनजाति शोध संस्थान से रिपोर्ट मांगी। शोध संस्थान ने अध्ययन के बाद सरकार को

सभी पक्षों की सुनवाई के बाद झारखंड सरकार का फैसला



लोहार प्रतिनिधियों की दलील : लोहार व लोहरा दोनों एक ही जाति हैं, जैसे अमरेजी में 'राजद' को 'राजदा' लिखा जाता है, वैसे ही सब के दौरान 'लोहार' को अमरेजी में 'लोहरा' लिखा गया।

एसटी समुदाय के प्रतिनिधियों ने कहा : सुनवाई के दौरान एसटी समुदाय के प्रतिनिधियों ने लोहार जाति की जीवन शैली और परंपराओं को लोहार (एसटी) से अलग बताया।

टीआरआर की रिपोर्ट में भी लोहार को एसटी का दर्जा नहीं देने की अनुशंसा की गयी

अमरी रिपोर्ट में भी लोहार को एसटी का दर्जा नहीं देने की अनुशंसा की गयी। लोहार और लोहरा को अलग-अलग जाति बताया और लोहार को एसटी का दर्जा नहीं देने की अनुशंसा की। इसके बाद सरकार ने इस मामले पर

पूर्व चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति अलतमस कबीर का निधन

संवाददाता : कोलकाता

देश के पूर्व चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति अलतमस कबीर का रविवार को देवघर में एक अस्पताल में निधन हो गया। 68 वर्षीय न्यायमूर्ति कबीर ने दो बच्चे कर 52 मिनट पर अंतिम

2005 में झारखंड हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं

68 वर्षीय न्यायमूर्ति कबीर का देहान्त कोलकाता में हुआ

यूपी चुनाव

69 सीटों पर 61 प्रतिशत वोट पड़े



सुनवाई शुरू की। सुनवाई के दौरान लोहार जाति के लोगों व प्रतिनिधियों के साथ ही एसटी समुदाय के सदस्यों को शामिल किया गया।

पीएसयू अफसरों का मूल वेतन ₹40 हजार करने की अनुशंसा

मनीष सिंह : रांची

भारत सरकार के 105 सर्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों (पीएसयू) के लिए गठित कमेटी ने पुनरीक्षित वेतनमान की अनुशंसा कर दी है। इसका लाभ झारखंड की कई कंपनियों के अधिकारियों को भी मिलेगा। वह वर्ष एक जनवरी 2017 से मिलना है। भारत सरकार की सर्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में काम करनेवाले अधिकारियों का यह वेतनमान पुनरीक्षित वेतनमान होगा। इसके लिए भारत सरकार ने जस्टिस (सैन) समिति चंद्र की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की थी। इसमें भारत सरकार के सेवानिवृत्त सचिव जुगल महापात्रा, इस्टीमेट और इकोनॉमिक ग्रुप के निदेशक प्रो मनोज पंडा व एनटीपीसी के पूर्व निदेशक शैलेंद्र पाल सिंह थे। कमेटी ने शिष्टाचार में अनेकाली कंपनियों के अधिकारियों के इंद्री लेवल (इ-0) का वर्तमान 12600-32500 से बढ़ा कर 30000-120000 रुपये करने की अनुशंसा की। वैसे करीब-करीब सभी कंपनियों में अपने इंद्री लेवल इ-1 रैंक में है। इस कारण अधिकारियों को नौकरी में योगदान करने के बाद ही 40 हजार रुपये के मूल वेतन का लाभ मिलने लगेगा। इ-9 रैंक के अधिकारियों का मूल वेतन 62 हजार रुपये से बढ़ा कर एक लाख 50 हजार रुपये करने की अनुशंसा की गयी है। सोमपरीडी का वेतन 80 हजार रुपये से बढ़ा कर दो लाख रुपये करने की अनुशंसा की गयी है।

सर्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के अधिकारियों का वेतन में करीब 15 फीसदी वृद्धि की अनुशंसा वर्तमान में की है। अभी अधिकारियों को करीब 120 फीसदी महंगाई भत्ता के रूप में मिल रहा है। कमेटी ने मूल वेतन और महंगाई भत्ता में करीब 15 फीसदी वृद्धि की अनुशंसा की है।

सर्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के अधिकारियों का वेतन में करीब 15 फीसदी वृद्धि की अनुशंसा वर्तमान में की है। अभी अधिकारियों को करीब 120 फीसदी महंगाई भत्ता के रूप में मिल रहा है। कमेटी ने मूल वेतन और महंगाई भत्ता में करीब 15 फीसदी वृद्धि की अनुशंसा की है।

सर्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के अधिकारियों का वेतन में करीब 15 फीसदी वृद्धि की अनुशंसा वर्तमान में की है। अभी अधिकारियों को करीब 120 फीसदी महंगाई भत्ता के रूप में मिल रहा है। कमेटी ने मूल वेतन और महंगाई भत्ता में करीब 15 फीसदी वृद्धि की अनुशंसा की है।

सर्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के अधिकारियों का वेतन में करीब 15 फीसदी वृद्धि की अनुशंसा वर्तमान में की है। अभी अधिकारियों को करीब 120 फीसदी महंगाई भत्ता के रूप में मिल रहा है। कमेटी ने मूल वेतन और महंगाई भत्ता में करीब 15 फीसदी वृद्धि की अनुशंसा की है।

सर्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के अधिकारियों का वेतन में करीब 15 फीसदी वृद्धि की अनुशंसा वर्तमान में की है। अभी अधिकारियों को करीब 120 फीसदी महंगाई भत्ता के रूप में मिल रहा है। कमेटी ने मूल वेतन और महंगाई भत्ता में करीब 15 फीसदी वृद्धि की अनुशंसा की है।

सर्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के अधिकारियों का वेतन में करीब 15 फीसदी वृद्धि की अनुशंसा वर्तमान में की है। अभी अधिकारियों को करीब 120 फीसदी महंगाई भत्ता के रूप में मिल रहा है। कमेटी ने मूल वेतन और महंगाई भत्ता में करीब 15 फीसदी वृद्धि की अनुशंसा की है।

सर्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के अधिकारियों का वेतन में करीब 15 फीसदी वृद्धि की अनुशंसा वर्तमान में की है। अभी अधिकारियों को करीब 120 फीसदी महंगाई भत्ता के रूप में मिल रहा है। कमेटी ने मूल वेतन और महंगाई भत्ता में करीब 15 फीसदी वृद्धि की अनुशंसा की है।

सर्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के अधिकारियों का वेतन में करीब 15 फीसदी वृद्धि की अनुशंसा वर्तमान में की है। अभी अधिकारियों को करीब 120 फीसदी महंगाई भत्ता के रूप में मिल रहा है। कमेटी ने मूल वेतन और महंगाई भत्ता में करीब 15 फीसदी वृद्धि की अनुशंसा की है।

सर्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के अधिकारियों का वेतन में करीब 15 फीसदी वृद्धि की अनुशंसा वर्तमान में की है। अभी अधिकारियों को करीब 120 फीसदी महंगाई भत्ता के रूप में मिल रहा है। कमेटी ने मूल वेतन और महंगाई भत्ता में करीब 15 फीसदी वृद्धि की अनुशंसा की है।

सर्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के अधिकारियों का वेतन में करीब 15 फीसदी वृद्धि की अनुशंसा वर्तमान में की है। अभी अधिकारियों को करीब 120 फीसदी महंगाई भत्ता के रूप में मिल रहा है। कमेटी ने मूल वेतन और महंगाई भत्ता में करीब 15 फीसदी वृद्धि की अनुशंसा की है।

सर्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के अधिकारियों का वेतन में करीब 15 फीसदी वृद्धि की अनुशंसा वर्तमान में की है। अभी अधिकारियों को करीब 120 फीसदी महंगाई भत्ता के रूप में मिल रहा है। कमेटी ने मूल वेतन और महंगाई भत्ता में करीब 15 फीसदी वृद्धि की अनुशंसा की है।

सर्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के अधिकारियों का वेतन में करीब 15 फीसदी वृद्धि की अनुशंसा वर्तमान में की है। अभी अधिकारियों को करीब 120 फीसदी महंगाई भत्ता के रूप में मिल रहा है। कमेटी ने मूल वेतन और महंगाई भत्ता में करीब 15 फीसदी वृद्धि की अनुशंसा की है।

सर्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के अधिकारियों का वेतन में करीब 15 फीसदी वृद्धि की अनुशंसा वर्तमान में की है। अभी अधिकारियों को करीब 120 फीसदी महंगाई भत्ता के रूप में मिल रहा है। कमेटी ने मूल वेतन और महंगाई भत्ता में करीब 15 फीसदी वृद्धि की अनुशंसा की है।

सर्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के अधिकारियों का वेतन में करीब 15 फीसदी वृद्धि की अनुशंसा वर्तमान में की है। अभी अधिकारियों को करीब 120 फीसदी महंगाई भत्ता के रूप में मिल रहा है। कमेटी ने मूल वेतन और महंगाई भत्ता में करीब 15 फीसदी वृद्धि की अनुशंसा की है।

सर्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के अधिकारियों का वेतन में करीब 15 फीसदी वृद्धि की अनुशंसा वर्तमान में की है। अभी अधिकारियों को करीब 120 फीसदी महंगाई भत्ता के रूप में मिल रहा है। कमेटी ने मूल वेतन और महंगाई भत्ता में करीब 15 फीसदी वृद्धि की अनुशंसा की है।

सर्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के अधिकारियों का वेतन में करीब 15 फीसदी वृद्धि की अनुशंसा वर्तमान में की है। अभी अधिकारियों को करीब 120 फीसदी महंगाई भत्ता के रूप में मिल रहा है। कमेटी ने मूल वेतन और महंगाई भत्ता में करीब 15 फीसदी वृद्धि की अनुशंसा की है।

सर्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के अधिकारियों का वेतन में करीब 15 फीसदी वृद्धि की अनुशंसा वर्तमान में की है। अभी अधिकारियों को करीब 120 फीसदी महंगाई भत्ता के रूप में मिल रहा है। कमेटी ने मूल वेतन और महंगाई भत्ता में करीब 15 फीसदी वृद्धि की अनुशंसा की है।

सर्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के अधिकारियों का वेतन में करीब 15 फीसदी वृद्धि की अनुशंसा वर्तमान में की है। अभी अधिकारियों को करीब 120 फीसदी महंगाई भत्ता के रूप में मिल रहा है। कमेटी ने मूल वेतन और महंगाई भत्ता में करीब 15 फीसदी वृद्धि की अनुशंसा की है।

सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के अधिकारियों का तीसरा पुनरीक्षित वेतनमान होगा

अभी 16,400 रुपये है मूल वेतन	एक नजर में पीएसयू 244 कुल सेंट्रल पीएसयू 105 में वेतन समझौता	और क्या-क्या सुविधा की अनुशंसा
25136.23 करोड़ रुपये वार्षिक वेतन	33103 अनुशंसा के बाद वेतन पर खर्च	- पारिवारिक भत्ता : मूल वेतन का 35 फीसदी - अतिरिक्त भत्ता : लोकेशन आधारित सौर, प्रोजेक्ट भत्ता, हाजीरा झुट्टी भत्ता - पीआरपी गणना की विधि में संशोधन - सेवानिवृत्ति सुविधा : मूल वेतन का 30 फीसदी और महंगाई भत्ता - मेडिकली की सीमा : 20 लाख तक - संवर्धन के बाद वित्तिय सुविधा के लिए हर साल प्रॉविडेंट फंडिंग देवस का तीन फीसदी - प्रवास भत्ता : मूल वेतन का 24, 16 व आठ फीसदी - अपीडी में इलाज के लिए प्रतिभाम एक हजार रुपये भत्ता - भरती होने की स्थिति में किसी भी इच्छा के अधीन की वैशाली पालिसी - बोर्ड लेवल अधिकारियों के लिए कॉर्पोरेट मेडरेशन (अधिकतम दो वलव के लिए)

अलग-अलग अधिवसुना जस्टी करणेची कंपनीय ■ अनुशंसा डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक वट्टाइनजान द्वारा अनुमोदित होने के बाद केंद्रीय कैबिनेट में जायेगा, केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद अलग-अलग कंपनीय आये-अपने स्तर से सरकारी संपत्ति अधिवसुना जारी करेगी, इसके बाद कंपनी स्तर पर ही अनुशंसा लगू हो सकेगी।

अवस्था	वर्तमान	अनुशंसा	इ-6	36600	90000
इ-0	12600	30000	इ-7	43200	100000
इ-1	16400	40000	इ-8	51300	120000
इ-2	20600	50000	इ-9	62200	140000
इ-3	24900	60000	निदेशक (सिडक)	75000	180000
इ-4	29100	70000	सीएमडी (सिडक)	80000	200000
इ-5	32900	80000			

■ **येक्यूटी का रॉशिया** 20 लाख रुबल से रोसनेमिष्ट्री के बाद वित्तीय सुविधा के लिए प्राइव प्रायिफ्ट फिफोर्टेस का नीचा पौहसी

■ **अवसर मंत्र** मुल वेतन का 24, 16 व आठ पीहसी.

■ **ओडी** में इलाज के लिए प्रति माह एक हजार रुपये मंत्र

■ **भरती होना की रीति** में फिरी भी इन्फोर्मेशन कंपनी की केशलेंस पौहसी.

■ **वर्ड लैबल अधिकारियों** के लिए कोरिप्टेड मेरिथिप (अधिकम दो वयव के लिए)

कमेटी ने अधिकारियों के वेतन में करीब 15 फीसदी वृद्धि की अनुशंसा वर्तमान में की है। अभी अधिकारियों को करीब 120 फीसदी महंगाई भत्ता के रूप में मिल रहा है। कमेटी ने मूल वेतन और महंगाई भत्ता में करीब 15 फीसदी वृद्धि की अनुशंसा की है।

सर्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के अधिकारियों का वेतन में करीब 15 फीसदी वृद्धि की अनुशंसा वर्तमान में की है। अभी अधिकारियों को करीब 120 फीसदी महंगाई भत्ता के रूप में मिल रहा है। कमेटी ने मूल वेतन और महंगाई भत्ता में करीब 15 फीसदी वृद्धि की अनुशंसा की है।

सर्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के अधिकारियों का वेतन में करीब 15 फीसदी वृद्धि की अनुशंसा वर्तमान में की है। अभी अधिकारियों को करीब 120 फीसदी महंगाई भत्ता के रूप में मिल रहा है। कमेटी ने मूल वेतन और महंगाई भत्ता में करीब 15 फीसदी वृद्धि की अनुशंसा की है।

सर्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के अधिकारियों का वेतन में करीब 15 फीसदी वृद्धि की अनुशंसा वर्तमान में की है। अभी अधिकारियों को करीब 120 फीसदी महंगाई भत्ता के रूप में मिल रहा है। कमेटी ने मूल वेतन और महंगाई भत्ता में करीब 15 फीसदी वृद्धि की अनुशंसा की है।

सर्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के अधिकारियों का वेतन में करीब 15 फीसदी वृद्धि की अनुशंसा वर्तमान में की है। अभी अधिकारियों को करीब 120 फीसदी महंगाई भत्ता के रूप में मिल रहा है। कमेटी ने मूल वेतन और महंगाई भत्ता में करीब 15 फीसदी वृद्धि की अनुशंसा की है।

सर्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के अधिकारियों का वेतन में करीब 15 फीसदी वृद्धि की अनुशंसा वर्तमान में की है। अभी अधिकारियों को करीब 120 फीसदी महंगाई भत्ता के रूप में मिल रहा है। कमेटी ने मूल वेतन और महंगाई भत्ता में करीब 15 फीसदी वृद्धि की अनुशंसा की है।

सर्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के अधिकारियों का वेतन में करीब 15 फीसदी वृद्धि की अनुशंसा वर्तमान में की है। अभी अधिकारियों को करीब 120 फीसदी महंगाई भत्ता के रूप में मिल रहा है। कमेटी ने मूल वेतन और महंगाई भत्ता में करीब 15 फीसदी वृद्धि की अनुशंसा की है।

सर्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के अधिकारियों का वेतन में करीब 15 फीसदी वृद्धि की अनुशंसा वर्तमान में की है। अभी अधिकारियों को करीब 120 फीसदी महंगाई भत्ता के रूप में मिल रहा है। कमेटी ने मूल वेतन और महंगाई भत्ता में करीब 15 फीसदी वृद्धि की अनुशंसा की है।

सर्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के अधिकारियों का वेतन में करीब 15 फीसदी वृद्धि की अनुशंसा वर्तमान में की है। अभी अधिकारियों को करीब 120 फीसदी महंगाई भत्ता के रूप में मिल रहा है। कमेटी ने मूल वेतन और महंगाई भत्ता में करीब 15 फीसदी वृद्धि की अनुशंसा की है।

सर्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के अधिकारियों का वेतन में करीब 15 फीसदी वृद्धि की अनुशंसा वर्तमान में की है। अभी अधिकारियों को करीब 120 फीसदी महंगाई भत्ता के रूप में मिल रहा है। कमेटी ने मूल वेतन और महंगाई भत्ता में करीब 15 फीसदी वृद्धि की अनुशंसा की है।

सर्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के अधिकारियों का वेतन में करीब 15 फीसदी वृद्धि की अनुशंसा वर्तमान में की है। अभी अधिकारियों को करीब 120 फीसदी महंगाई भत्ता के रूप में मिल रहा है। कमेटी ने मूल वेतन और महंगाई भत्ता में करीब 15 फीसदी वृद्धि की अनुशंसा की है।

सर्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के अधिकारियों का वेतन में करीब 15 फीसदी वृद्धि की अनुशंसा वर्तमान में की है। अभी अधिकारियों को करीब 120 फीसदी महंगाई भत्ता के रूप में मिल रहा है। कमेटी ने मूल वेतन और महंगाई भत्ता में करीब 15 फीसदी वृद्धि की अनुशंसा की है।

सर्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के अधिकारियों का वेतन में करीब 15 फीसदी वृद्धि की अनुशंसा वर्तमान में की है। अभी अधिकारियों को करीब 120 फीसदी महंगाई भत्ता के रूप में मिल रहा है। कमेटी ने मूल वेतन और महंगाई भत्ता में करीब 15 फीसदी वृद्धि की अनुशंसा की है।

सर्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के अधिकारियों का वेतन में करीब 15 फीसदी वृद्धि की अनुशंसा वर्तमान में की है। अभी अधिकारियों को करीब 120 फीसदी महंगाई भत्ता के रूप में मिल रहा है। कमेटी ने मूल वेतन और महंगाई भत्ता में करीब 15 फीसदी वृद्धि की अनुशंसा की है।

सर्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के अधिकारियों का वेतन में करीब 15 फीसदी वृद्धि की अनुशंसा वर्तमान में की है। अभी अधिकारियों को करीब 120 फीसदी महंगाई भत्ता के रूप में मिल रहा है। कमेटी ने मूल वेतन और महंगाई भत्ता में करीब 15 फीसदी वृद्धि की अनुशंसा की है।

सर्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के अधिकारियों का वेतन में करीब 15 फीसदी वृद्धि की अनुशंसा वर्तमान में की है। अभी अधिकारियों को करीब 120 फीसदी महंगाई भत्ता के रूप में मिल रहा है। कमेटी ने मूल वेतन और महंगाई भत्ता में करीब 15 फीसदी वृद्धि की अनुशंसा की है।

सर्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के अधिकारियों का वेतन में करीब 15 फीसदी वृद्धि की अनुशंसा वर्तमान में की है। अभी अधिकारियों को करीब 120 फीसदी महंगाई भत्ता के रूप में मिल रहा है। कमेटी ने मूल वेतन और महंगाई भत्ता में करीब 15 फीसदी वृद्धि की अनुशंसा की है।

Highest Result Producing Institute of Ranchi

Since 16 Years For

MEDICAL Entrance Exam.

The Best Education System Under One Campus is going to Start from April '2017 at Hinoo, Ranchi

- 10,000 Sq.ft. Campus With Centralized A.C. & Wi-Fi
- Doubt removal counters on every floor in the building
- 32,00 sqft. Parking Area
- Canteen facility with Snacks & Juice Parlor
- Residential hostel facilities
- A.C. Library facilities
- Audio & Visual Class Room
- Hi-tech Sensitive Security System to ensure safe surroundings & in-campus

SPOT TEST Next Test on

Feedback

readwhere

http://www.readwhere.com



Feedback

